an>

Title: Need to release relief fund to Bihar for rehabilitation of people distressed due to loss of life and property caused by floods in the State.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) ः अगस्त-सितम्बर, 2016 में गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिससे बिहार राज्य को काफी जान-माल एवं आर्थिक क्षति हुई है। गंगा इस वर्ष पूर्ण उफान पर थी और इससे नदी किनारे बसे शहर-गांव और खेत-खलिहान को काफी नुकसान पहँचा। करीब 300 से अधिक लोगों की जाने गइप। वे डूब गये या पानी में बह गये पता नहीं चला। लहलहाती फसल पानी की चपेट में आकर नष्ट हो गई। लाखों घर पानी में बह गये। सड़कें, पुल-पुलिया और परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रेल की पटरियां भी बाढ़ की चपेट में आ गइप। सबसे अधिक किसानों को हानि हुई, जिनकी फसलें नष्ट हो गइप। आपदा विभाग ने 22 सितम्बर, 2016 को ही 4,111.98 करोड़ रूपये की हुई हानि का विस्तृत ब्यौरा केन्द्र सरकार के पास भेज दिया। फिर भी पिछले लगभग दो महीनों में केन्द्रीय टीम बिहार आकर क्षति का आकलन नहीं कर सकी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस संबंध में माननीय गृहमंत्री को पत्र भी भेजा। बाढ़ से हुई व्यापक क्षति के बारे में अवगत भी कराया। साथ ही 23 अगस्त, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तु-स्थिति की जानकारी दी। माननीय गृहमंत्री जी से भी मिले, किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सर्वसम्मति से अनुमोदित बिहार विधान सभा का प्रस्ताव ""बिहार को विशेष राज्य का दर्जा"" देने की मांग को अनसुना कर और बाढ़ से इस वर्ष हुई भयंकर क्षति के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

अब केन्द्र सरकार वहां टीम भेजने की बात सोच रही है। कई बार तिथि निर्धारित कर रद्द भी कर चुकी है। इतने दिनों बाद जब किसान अपनी अगली फसलों की बुआई कर चुके हैं। घर की मरम्मत या बना रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल-पुलिया बनाये जा रहे हैं, फिर केन्द्रीय टीम के दौरे का क्या औचित्य रह जाता है? अब ऐसी परिस्थिति में क्षति का आकलन करने में कठिनाई नहीं होगी? वैसे ही बिहार गरीब राज्यों की श्रेणी में निचले पायदान पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार दोहराते हैं कि बिहार का विकास सरकार की प्राथमिकता में है, तो फिर क्या यही प्राथमिकता का पैमाना है? अतः आग्रह है कि राज्य को क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार सहायता राशि के रूप में 4,111.98 करोड़ रूपये जल्द से जल्द निर्गत करे।